

अध्याय 1: वित्तीय बाजार का परिचय

(Unit 1: Introduction to Financial Market in English and Hindi)

वित्तीय बाजार की परिभाषा(Definition of Financial Market):

वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ धन का लेन-देन होता है। यह वह स्थान होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों की खरीद-बिक्री की जाती है। इन बाजारों में पूंजी की मांग करने वाले (जैसे कंपनियाँ, सरकारें) और पूंजी की आपूर्ति करने वाले (जैसे निवेशक, बैंक) एक-दूसरे से मिलते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित होता है।

वित्तीय बाजारों की मदद से निवेशक अपने पैसे को लाभदायक साधनों में निवेश कर सकते हैं और व्यवसायों को अपने विकास के लिए आवश्यक धन प्राप्त होता है। वित्तीय बाजार पूंजी निर्माण में, तरलता (Liquidity) उपलब्ध कराने में, मूल्य निर्धारण में तथा जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वित्तीय बाजार के प्रमुख प्रकार:

- मुद्रा बाजार (Money Market):** यह अल्पकालिक वित्तीय उपकरणों का बाजार है जहाँ 1 वर्ष से कम अवधि वाले ऋण उपकरणों की खरीद-बिक्री होती है। जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर आदि।
- पूंजी बाजार (Capital Market):** यह दीर्घकालिक निवेश के लिए होता है, जहाँ कंपनियाँ और सरकारें दीर्घकालिक पूंजी जुटाती हैं। इसमें इक्विटी और डेट मार्केट शामिल हैं।
- प्राथमिक बाजार (Primary Market):** इसमें नए वित्तीय उपकरण जारी किए जाते हैं जैसे कि IPO (Initial Public Offering)।
- द्वितीयक बाजार (Secondary Market):** यहाँ पहले से जारी वित्तीय उपकरणों की खरीद-बिक्री होती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों का व्यापार।

वित्तीय उपकरण की परिभाषा (Definition of Financial Instruments in Hindi):

वित्तीय उपकरण वे दस्तावेज़ या अनुबंध होते हैं जो वित्तीय परिसंपत्तियों या दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वह साधन होते हैं जिनके माध्यम से पूंजी या ऋण का लेन-देन

होता है। वित्तीय उपकरण निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच एक माध्यम का कार्य करते हैं।

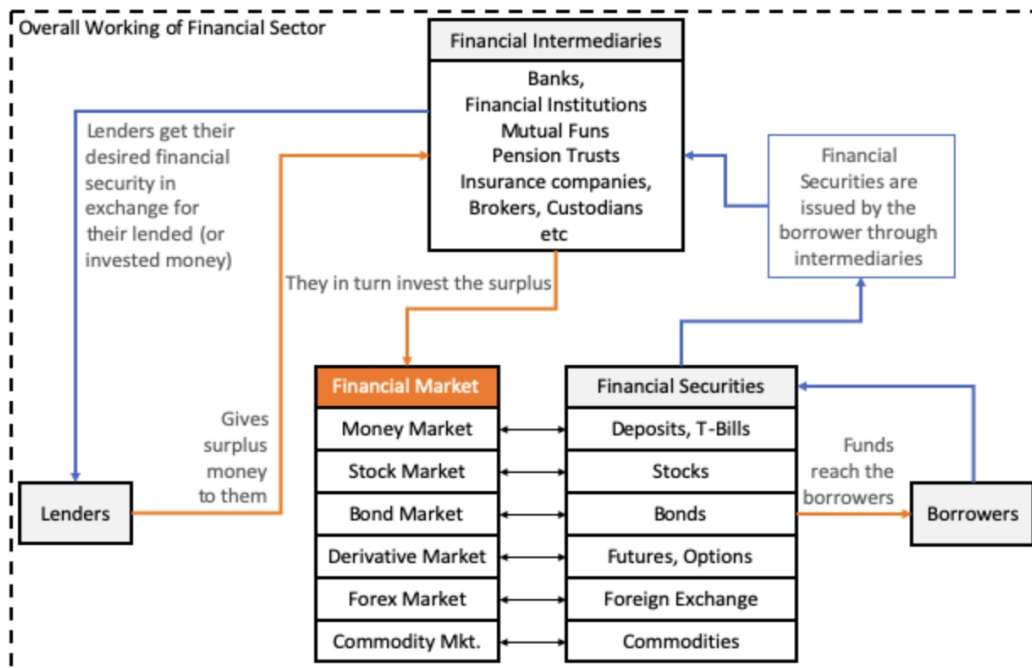
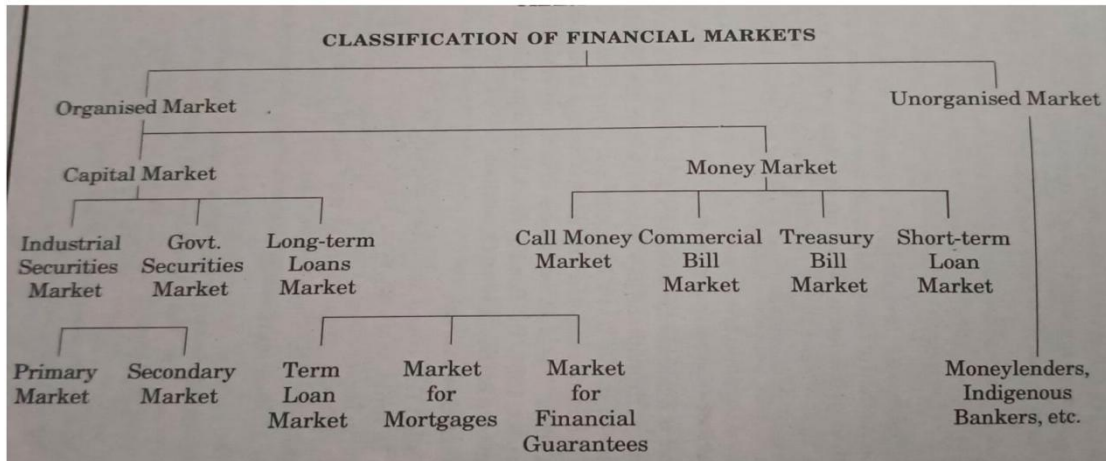
वित्तीय उपकरणों के प्रमुख प्रकार:

1. **इक्विटी इंस्ट्रूमेंट (Equity Instruments):** ये ऐसे उपकरण हैं जो किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे – शेयर (Shares)।
2. **डेट इंस्ट्रूमेंट (Debt Instruments):** ये वे उपकरण होते हैं जिनमें उधारकर्ता, निवेशक को निश्चित समय पर ब्याज और मूलधन चुकाने का वादा करता है। जैसे – बॉन्ड, डिबेंचर।
3. **डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (Derivative Instruments):** ये ऐसे उपकरण हैं जिनका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति (जैसे स्टॉक, मुद्रा, कमोडिटी) के मूल्य पर आधारित होता है। जैसे – फ्यूचर्स, ऑप्शन्स।
4. **हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट (Hybrid Instruments):** इनमें इक्विटी और डेट दोनों के गुण होते हैं। जैसे – कन्वर्टिबल डिबेंचर।

इन उपकरणों का उपयोग निवेश, बचत, जोखिम प्रबंधन और पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति बाज़ार का वर्णन (Description of Indian Securities Market in Hindi):

भारतीय प्रतिभूति बाज़ार भारत की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वह बाज़ार है जहाँ कंपनियाँ, सरकारें और अन्य संस्थाएँ निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड) जारी करती हैं। इस बाज़ार का संचालन और निगरानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI – Securities and Exchange Board of India) द्वारा की जाती है।



भारतीय प्रतिभूति बाज़ार के प्रमुख घटक:

1. प्राथमिक बाज़ार (Primary Market):

इस बाज़ार में कंपनियाँ पहली बार नए प्रतिभूति (जैसे शेयर या बॉन्ड) जारी करती हैं। निवेशक सीधे कंपनी से प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं। उदाहरण: IPO (Initial Public Offering)।

2. द्वितीयक बाज़ार (Secondary Market):

यहाँ पहले से जारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री होती है। यह लेन-देन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं:

- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)

3. डेरिवेटिव बाज़ार:

यहाँ डेरिवेटिव उत्पादों जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शन्स का व्यापार होता है। यह निवेशकों को हेजिंग और सट्टा (Speculation) की सुविधा प्रदान करता है।

4. बॉन्ड मार्केट:

यह बाज़ार ऋण प्रतिभूतियों के लिए होता है जैसे कि सरकारी बॉन्ड, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर आदि।

भारतीय प्रतिभूति बाज़ार की विशेषताएँ:

1. **विनियमन (Regulation):** भारतीय प्रतिभूति बाज़ार का नियंत्रण SEBI द्वारा किया जाता है। SEBI का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और बाज़ार में पारदर्शिता बनाए रखना है।
2. **तकनीकी विकास:** NSE और BSE ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, जिससे लेन-देन तीव्र, सटीक और पारदर्शी हो गया है।
3. **विदेशी निवेश:** भारत ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के लिए बाज़ार खोला है, जिससे विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ा है।
4. **लिक्विडिटी:** भारतीय प्रतिभूति बाज़ार में उच्च तरलता है, जिससे निवेशक आसानी से प्रतिभूतियों को खरीद या बेच सकते हैं।
5. **निवेशक सुरक्षा:** SEBI और अन्य संस्थाएं निवेशकों को जागरूक करने, धोखाधड़ी रोकने और विवाद निपटाने के लिए नियम और तंत्र विकसित करती हैं।

भारतीय प्रतिभूति बाज़ार की चुनौतियाँ:

1. **मूल्य में अत्यधिक अस्थिरता (Volatility):** शेयर बाज़ार में अक्सर तेज़ उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है जिससे छोटे निवेशक प्रभावित हो सकते हैं।
2. **कम निवेश जागरूकता:** ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में निवेशकों की संख्या अभी भी सीमित है।

3. **घोटाले और धोखाधड़ी:** यद्यपि SEBI सख्ती से कार्य करती है, फिर भी कभी-कभी निवेश घोटाले सामने आते हैं।
4. **तकनीकी साक्षरता की कमी:** इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली का लाभ उठाने के लिए तकनीकी समझ आवश्यक है, जो सभी निवेशकों में नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion):

भारतीय वित्तीय प्रणाली में वित्तीय बाज़ार और वित्तीय उपकरणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संसाधनों के कुशल आवंटन, निवेश के अवसरों और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय प्रतिभूति बाज़ार ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

हालाँकि, इस बाज़ार को और अधिक समावेशी और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है ताकि देश के सभी नागरिक, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोग, इसके लाभों से वंचित न रहें। सरकार, SEBI और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मिलकर एक पारदर्शी, प्रभावी और निवेशक-अनुकूल प्रणाली सुनिश्चित करनी होगी।

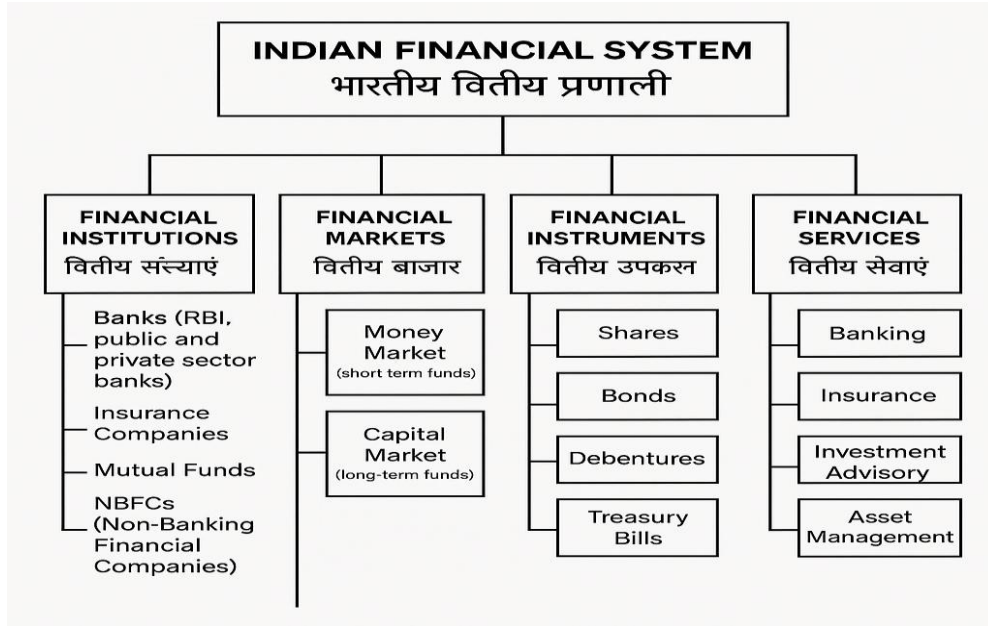
Overview of Indian Financial System

The Indian Financial System refers to the network of institutions, markets, instruments, and services that facilitate the flow of funds within the economy. It plays a critical role in mobilizing savings, allocating resources, and supporting economic growth.

Main Components of the Indian Financial System:

1. **Financial Institutions** – These include banks (like RBI, public and private sector banks), insurance companies, mutual funds, and NBFCs (Non-Banking Financial Companies).
2. **Financial Markets** – These are platforms for buying and selling financial assets. They are broadly divided into:
 - **Money Market** (short-term funds)
 - **Capital Market** (long-term funds)
3. **Financial Instruments** – These include shares, bonds, debentures, treasury bills, etc., which represent financial claims.
4. **Financial Services** – Services such as banking, insurance, investment advisory, and asset management that support financial transactions.

The Reserve Bank of India (RBI) is the central authority that regulates and supervises the financial system in India.



भारतीय वित्तीय प्रणाली उस नेटवर्क को दर्शाती है जिसमें संस्थाएं, बाजार, उपकरण और सेवाएं शामिल होती हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को सुगम बनाती हैं। यह प्रणाली बचत को संगठित करने, संसाधनों के आवंटन और आर्थिक विकास में सहायक होती है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुख्य घटक:

1. **वित्तीय संस्थाएं** – जैसे कि बैंक (आरबीआई, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक), बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड्स, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs)।
2. **वित्तीय बाजार** – यह वे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ वित्तीय संपत्तियों की खरीद-बिक्री होती है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं:
 - **मनी मार्केट** (अल्पकालिक निधियाँ)
 - **कैपिटल मार्केट** (दीर्घकालिक निधियाँ)
3. **वित्तीय उपकरण** – जैसे कि शेयर, बांड, डिबेंचर, ट्रेज़री बिल आदि, जो वित्तीय दावे को दर्शाते हैं।
4. **वित्तीय सेवाएं** – जैसे बैंकिंग, बीमा, निवेश सलाह, और संपत्ति प्रबंधन सेवाएं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इस संपूर्ण प्रणाली का केंद्रीय नियामक और पर्यवेक्षक है।

Financial Sector Reforms in India

Objective: To make the financial sector more efficient, competitive, and transparent, especially post-1991 liberalization.

Key Financial Reforms Since 1991:

1. **Banking Reforms**
 - Deregulation of interest rates
 - Reduction in SLR and CRR
 - Introduction of prudential norms (NPA recognition, capital adequacy)
 - Entry of private sector banks (like ICICI, HDFC Bank)
2. **Capital Market Reforms**
 - Formation of SEBI as a regulator
 - Dematerialization of shares
 - Online trading system (NSE, BSE modernization)
3. **Insurance Sector Reforms**
 - Opening up to private players (e.g., ICICI Prudential, HDFC Life)
 - IRDAI formed as regulator
4. **Pension Sector Reforms**
 - National Pension Scheme (NPS) introduced
 - Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) established
5. **Financial Inclusion Measures**
 - Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
 - Direct Benefit Transfer (DBT)
 - Microfinance institutions and self-help groups (SHGs)
6. **Digital Reforms**
 - UPI, BHIM, Mobile wallets
 - Digital KYC, Aadhaar linking

भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार

उद्देश्य: वित्तीय क्षेत्र को कुशल, प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी बनाना।

1991 के बाद प्रमुख सुधार:

1. **बैंकिंग सुधार**
 - ब्याज दरों का विनियमन समाप्त
 - SLR और CRR में कटौती
 - एनपीए मान्यता और पूंजी पर्याप्तता के मानदंड
 - निजी बैंकों का प्रवेश (जैसे ICICI, HDFC Bank)
2. **पूंजी बाजार सुधार**
 - SEBI की स्थापना
 - शेयरों का डिमैट रूप में लेन-देन
 - ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम
3. **बीमा क्षेत्र सुधार**
 - निजी कंपनियों को अनुमति
 - IRDAI की स्थापना
4. **पेंशन सुधार**

- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
- PFRDA की स्थापना
- 5. **वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)**
 - जन धन योजना
 - डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
 - माइक्रोफाइनेंस और SHG
- 6. **डिजिटल सुधार**
 - UPI, भीम ऐप, मोबाइल वॉलेट
 - डिजिटल केवाईसी, आधार लिंकिंग